विधि एवं न्याय मंत्रालय

मांग संख्या 62

विधि एवं न्याय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		बजट, 2008-2009			संशोधित, 2008-2009			बजट, 2009-2010		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		260.00	425.84	685.84	160.00	590.71	750.71	260.00	1377.11	1637.11
पूंजी		...	*0.03*	*0.03*	...	*0.29*	*0.29*	...	*40.89*	*40.89*
जोड़		**260.00**	**425.87**	**685.87**	**160.00**	**591.00**	**751.00**	**260.00**	**1418.00**	**1678.00**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं										
1.01 विधि कार्य विभाग	2052	...	22.98	22.98	...	27.70	27.70	...	33.20	33.20
1.02 विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफई)	2052	...	0.68	0.68	...	0.86	0.86	...	1.09	1.09
1.03 विधायी विभाग	2052	...	7.02	7.02	...	9.47	9.47	...	12.36	12.36
1.04 न्याय विभाग	2052	...	1.04	1.04	...	1.58	1.58	...	1.81	1.81
1.05 अन्य	2052	...	6.54	6.54	...	8.25	8.25	...	10.30	10.30
	जोड़	...	*38.26*	*38.26*	...	*47.86*	*47.86*	...	*58.76*	*58.76*
2. राज्य चुनाव के अंग										
2.01 चुनाव	2015	...	20.00	20.00	...	17.20	17.20	...	850.00	850.00
2.02 सामान्य चुनावी खर्च	2015	...	175.34	175.34	...	349.75	349.75	...	227.00	227.00
2.03 मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना	2015	...	23.66	23.66	...	21.11	21.11	...	43.00	43.00
	जोड़	...	219.00	219.00	...	388.06	388.06	...	1120.00	1120.00
3. राजकोषीय सेवाएं										
3.01 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	2020	...	29.07	29.07	...	33.24	33.24	...	43.62	43.62
3.02 राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण	2020	...	0.24	0.24	...	0.08	0.08	...	0.14	0.14
	जोड़	...	*29.31*	*29.31*	...	*33.32*	*33.32*	...	*43.76*	*43.76*
4. न्याय प्रशासन										
4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	2014	...	8.60	8.60	...	8.91	8.91	...	13.40	13.40
4.02 जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण	2014	115.00	...	115.00	49.50	...	49.50	110.00	...	110.00
4.03 विशेष न्यायालय	3601	...	13.00	13.00	...	1.50	1.50	...	10.00	10.00
4.04 फास्ट ट्रैक न्यायालय	2014	...	...	...	...	60.56	60.56	...	75.00	75.00
	3601	...	75.00	75.00	...		...	...	...	...
	जोड़	...	*75.00*	*75.00*	...	*60.56*	*60.56*	...	*75.00*	*75.00*
4.05 न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधा हेतु विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता-अनुदान	2014	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...	...
4.06 अन्य व्यय	2014	...	36.52	36.52	...	34.79	34.79	...	40.81	40.81
4.07 भारत में न्याय तक पहुंच का सुदृढ़ीकरण	2014	...	...	...	...	...	...	8.50	...	8.50
4.08 न्याय प्रशासन परियोजना	2014	1.00	...	1.00	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50
4.09 न्यायिक सुधारों तथा निर्धारण प्रास्थिति का अध्ययन	2014	1.00	...	1.00	0.45	...	0.45	4.50	...	4.50
4.10 अन्तर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र	2014	...	...	...	...	6.34	6.34	...	6.25	6.25
4.11 ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता	2014	...	...	...	...	...	...	0.90	...	0.90
	जोड़	*120.00*	*133.12*	*253.12*	*53.00*	*112.10*	*165.10*	*124.40*	*145.46*	*269.86*
5. अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
5.01 न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं	3601	111.00	...	111.00	88.00	...	88.00	109.60	...	109.60

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5.02 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता-अनुदान	3602	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...	...
5.03 अन्य कार्यक्रम	2070	...	6.15	6.15	...	8.29	8.29	...	9.13	9.13
5.04 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070	...	0.03	0.03	...	0.29	0.29	...	40.89	40.89
	जोड़	*114.00*	*6.18*	*120.18*	*91.00*	*8.58*	*99.58*	*109.60*	*50.02*	*159.62*
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	26.00	...	26.00	16.00	1.08	17.08	26.00	...	26.00
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	26.00	...	26.00	16.00	1.08	17.08	26.00	...	26.00
कुल जोड़		***260.00***	***425.87***	***685.87***	***160.00***	***591.00***	***751.00***	***260.00***	***1418.00***	***1678.00***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. न्याय प्रशासन	32014	234.00	...	234.00	144.00	...	144.00	234.00	...	234.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	26.00	...	26.00	16.00	...	16.00	26.00	...	26.00
जोड़		**260.00**	**...**	**260.00**	**160.00**	**...**	**160.00**	**260.00**	**...**	**260.00**

1.01- 1.04 इसमें विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के सचिवालय व्यय तथा विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

1.05 यह प्रावधान, राजभाषा खण्ड, जो केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उनके मुद्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संगठित मुकदमा अभिकरण, जो केन्द्रीय अभिकरण की योजना में सम्मिलित केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है, के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है।

2.01 यह प्रावधान 15वीं लोक सभा के आम चुनावों की बकाया देनदारी को वहन करने के लिए है।

2.02 यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को चुनाव व्यय से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है। इसमें मतदाता सूचियों आदि की तैयारी और मुद्रण की लागत भी शामिल है।

2.03 यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने पर हुए व्यय के सम्बन्ध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है।

3.01 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना मुख्य आयकर आयुक्तों, आयकर महानिदेशकों, आयकर आयुक्तों, आयकर आयुक्तों (अपील) और आयकर उपायुक्तों (अपील) के निर्णयों और आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए आयकर अधिनयम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई है।

3.02 राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना, प्रत्यक्ष करों की वसूली, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन तथा सेवाओं पर कर वसूली एवं माल पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों और ऐसे कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल की कीमत संबंधी विवादों के न्याय-निर्णयन हेतु की गई है।

4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी 17 अगस्त, 1993 से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई थी। यह प्रावधान अकादमी के आवर्ती व्यय की पूर्ति हेतु किया गया है।

4.02 यह प्रावधान जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण पर व्यय हेतु किया गया है।

4.03 यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार न्यायालयों पर होने वाले व्यय के लिए किया गया है।

4.04 यह प्रावधान (31.03.2005 के बाद भी जारी) 1562 फास्ट ट्रैक न्यायालयों के आवर्ती तथा गैर - आवर्ती व्यय को वहन करने के लिए है।

4.05 यह प्रावधान विधान मण्डल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है।

4.06 यह प्रावधान विधि अधिकारी, विधि सलाहकारों तथा परामर्शियों के लिए तथा राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) के माध्यम से गरीबों के लिए विधिक सहायता के लिए भी है।

4.07 यह प्रावधान मुख्यतः भारत में न्याय अभिगम सुदृढ़ करने के संबंध में न्याय विभाग द्वारा यूएनडीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए है।

4.08 यह प्रावधान मुख्यतः न्याय प्रशासन के संबंध में न्याय विभाग द्वारा एशियाई विकास बैंक परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित है।

4.09 यह प्रावधान न्यायिक सुधार संबंधी व्यवस्थित अध्ययन को अपनाने हेतु है।

4.10 यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र को विवादों का शीघ्रता से समाधान करना सुकर बनाने और न्यायालय में कार्यक्षेत्र कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रविधियों का संवर्धन, आयोजन और प्रचार करने के लिए नई दिल्ली में सम्मेलन केन्द्र, व्यापार केन्द्र और फ्यूचर ब्लॉक के निर्माण के लिए है।

5.01-5.02 यह प्रावधान न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना हेतु और विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुदान/सहायता प्रदान करने के लिए है।

5.03 यह प्रावधान विधि आयोग, अंतराष्ट्रीय विधि संघ के लिए और विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा कानूनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने के लिए किया गया है।

5.04 यह प्रावधान विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों तथा राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण तथा भवनों के निर्माण के लिए है।

6. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए है।